भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-121

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

तमिलनाडु में उन्नत भारत अभियान का आकलन और कार्यान्वयन

†*121. **श्री मलैयारासन डी.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों में सतत ग्रामीण विकास के लिए उन्नत भारत अभियान (यूबीए) की प्रगति और प्रभावकारिता का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु से यूबीए 1.0 और यूबीए 2.0 के अंतर्गत कितने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का चयन किया गया है;

(ग) क्या भागीदार संस्थानों को आवंटित धनराशि पर्याप्त है और समयबद्ध तरीके से जारी की गई है, यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अभियान के अंतर्गत तमिलनाडु में बेहतर आजीविका, डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण अवसंरचना या क्षमता निर्माण जैसे मापनीय सामाजिक-आर्थिक परिणाम हासिल हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने, संस्थागत सहायता में वृद्धि करने और इस कार्यक्रम का विस्तार और अधिक ग्रामीण संकुलों तक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

“तमिलनाडु में उन्नत भारत अभियान का आकलन और कार्यान्वयन” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री मलैयारासन डी. द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 121 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): उन्नत भारत अभियान (यूबीए) शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसे सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। यह ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई), जिन्हें प्रतिभागी संस्थान (पीआई) भी कहा जाता है, को गांवों और स्थानीय समुदायों से जोड़ता है। यूबीए का उद्देश्य छात्रों को ग्रामीण समुदायों और अन्य सरकारी संगठनों के करीब लाना है जिसका अंतिम लक्ष्य गांवों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना है। इसने गांवों में काम करने के लिए हितधारकों जैसे एचईआई, सरकारी संगठनों, युवाओं, गैर सरकारी संगठनों आदि का एक विस्तृत नेटवर्क बनाया है। यह योजना उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों को गांवों के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है और उन्हें इन समस्याओं के व्यवहार्य समाधान विकसित करने के लिए गांवों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

यूबीए 1.0 और यूबीए 2.0 के तहत, तमिलनाडु राज्य में, इस योजना के तहत 3120 गांवों को शामिल करते हुए 624 उच्चतर शिक्षा संस्थानों का नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त, 213 प्रौद्योगिकी-आधारित, प्रबंधकीय और सामाजिक मध्यवर्तनों को यूबीए के तहत कार्यान्वित किया गया है जो रोजगार वृद्धि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, डिजिटल शिक्षा और क्षमता वृद्धि में योगदान दे रहे हैं।

सरकार यूबीए के तहत पीआई को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है और इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से और समय पर निधियां जारी की गई हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान, यूबीए योजना के तहत कुल 33.70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

सरकार ने स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर आवधिक राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के माध्यम से यूबीए की प्रगति और प्रभावशीलता का आकलन किया है। इस योजना का मूल्यांकन सबसे पहले वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा किया गया था। इसका पुनर्मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा वर्ष 2025-26 में किया गया है। इन मूल्यांकनों में दक्षिणी राज्यों और तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को शामिल किया गया है, और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यूबीए एक अत्यधिक प्रासंगिक और प्रभावी कार्यक्रम है, जो

जमीनी स्तर के ग्रामीण विकास के साथ अकादमिक उद्देश्यों को विशेष रूप से जोड़ता है। यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि इस योजना ने प्रतिभागी शासन, सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक नवाचार के लिए एक मजबूत आधार बनाया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली यूबीए का राष्ट्रीय समन्वय संस्थान (एनसीआई) है जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों का क्षेत्र-विशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने वाले 50 क्षेत्रीय समन्वय संस्थानों (आरसीआई) के साथ-साथ इस योजना के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। एनसीआई (आईआईटी दिल्ली) यूबीए की समग्र निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस योजना को क्षेत्रीय समन्वय संस्थानों (आरसीआई) और विषय विशेषज्ञ समूहों (एसईजी) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है और निगरानी को सुदृढ़ करने और अपेक्षाकृत अधिक ग्रामीण समूहों तक कवरेज बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ समन्वय किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से जिला स्तर पर नरेगा को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार जिला समाहर्त्ताओं/जिला दंडाधिकारियों/अन्य संबंधित अधिकारियों के माध्यम से यूबीए योजना के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। अपेक्षाकृत अधिक ग्रामीण समूहों में कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए, सरकार यूबीए के तहत लगे संस्थानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित रूप से संवाद करके इस योजना को बढ़ावा दे रही है।

*****